(b) Results of any such surveys are not available. However, the Government have adopted an integrated approach and policy and taken a number of legal, welfare and awareness building measures to counteract the problem of drug abuse.

Drought in Uttar Pradesh

1730. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment of the damage to the Kharif crop as a result of severe drought in many districts of Uttar Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether the Chief Minister of Uttar Pradesh have requested for Central assistance to the tune of rupees 470 crores for fighting drought situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) In their memorandum seeking Central assistance for expenditure of Rs. 474.82 crores for tackling drought in some parts of the State, the Government of Uttar Pradesh have reported that 72 lakh hectares of cropped area has been affected by drought. A Central Team has already visited the State for making an assessment of the situation.

दूध की मांग

1731. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनसंख्या के हिसाब से दूध की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) देश में अनुमानत: कितना दूध उपलब्ध है ;

(ग) यदि दूध की कोई कमी है तो इसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) दूध तैयार करने के लिए विदेशों से नि:शुल्क मिलने वाला 15 करोड़ रुपए मूल्य का दुग्ध चूर्ण तथा नि:शुल्क बटर आयल कब तक मिलता रहेगा और उस अवधि के पश्चात् सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट (1976) के अनुसार वर्ष 1985 में दूध के मांग-प्रक्षेपण का उच्च और निम्न स्तर क्रमश: 442 और 334 लाख मीटरी टन है। अत: वर्ष 1985 की औसत मांग 388 लाख मीटरी टन मानी जा सकती है।

(ख) 1985-86 के दौरान देश में प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन 423 लाख मीटरी टन है।

(ग) दूध की मांग को मुख्यत: पूरा कर लिया गया है। फिर भी सरकार ने आपरेशन फ्लड परियोजना सहित केन्द्रीय, केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य की प्लान स्कीमों के जरिए देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अनेक उपाय किये हैं। ये उपाय हैं :— अनजानी नस्ल के गो-पशुओं का डेरी की विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन और देशी गो-पशुओं और भैंसों के चुनींदा प्रजनन के जरिए दुग्ध उत्पादन की क्षमता में सुधार करना, संक्रामक रोगों के नियन्त्रण सहित स्वास्थ्य के पर्याप्त प्रबंध, आहार/चारे के संसाधनों के विकास के माध्यम से पोषक तत्वों में सुधार करना और दुग्ध विपणन की सुनिश्चित सुविधाओं का सृजन करना।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के खाद्य-सहायता कार्यक्रम 1985 से आगे आपरेशन फ्लड चरण 3 के लिये दुग्ध चूर्ण की सप्लाई करने के लिये अभी तक कोई ठोस वादा नहीं किया है। तथापि भविष्य में स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल/बटर का आयात करनें के बारे में सरकार की नीति इस संबंध में प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।